कायम रहे नदियों की निर्मलता

साझा गुप्ता
प्रोग्राम एसोसिएट, सीईईडब्ल्यू

नितिन वरसी
सीनियर प्रोग्राम लीड, सीईईडब्ल्यू

भारत की लगभग आधी नदियां प्रदूषित हैं। इनमें गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी नदियां भी शामिल हैं। अधिकांश नदियों में उच्च प्रदूषण स्तर का मुख्य कारण इनमें मिलने वाला कूड़ा-कचरा और घरेलू अपशिष्ट जल है। उदाहरण के लिए, दिल्ली पार करते समय यमुना जल की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। नदियों को निर्मल बनाने के लिए इसमें अपशिष्ट मिलने की बढ़ती समस्या का समाधान आवश्यक है।

वैसे हमारे देश में जल प्रदूषण कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। पहला कदम वर्ष 2021 में पांच सौ शहरों में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत 2.0) की शुरुआत है। इसका लक्ष्य उपचारित अपशिष्ट जल को दोबारा उपयोग करके शहर में 20 प्रतिशत पानी की मांग को पूरा करना है। दूसरा कदम, गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए संचालित 'नमामि गंगे' कार्यक्रम है। इसमें अपशिष्ट जल शोधन के बुनियादी ढांचे के विकास और उपचारित जल के दोबारा उपयोग से शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व सृजन और नदियों के विकास को पर जोर दिया गया है। तीसरा कदम, पिछले साल शुरू हुआ अमृत सरोवर मिशन है, जो 50 हजार तालाबों के कायाकल्प या निर्माण का अपना राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा कर चुका है और अतिरिक्त 50 हजार तालाबों के निर्माण के लिए काम कर रहा है।

काउंसिल आन एनर्जी, इनवायरमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2050 तक प्रतिदिन सौ अरब लीटर से अधिक उपचारित जल उपलब्ध होगा, जिसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। हालांकि उपचारित जल के उपयोग को मुख्यधारा में लाने और उस स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां पर यह स्वच्छ जल की मांग घटा सके। इसके लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं।

जल नीतियों, कार्यक्रमों व सरकार के विभिन्न स्तरों में तालमेल जरूरी है, ताकि संसाधनों के उपयोग और निवेश पर लाभ को अधिकतम बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, ठोस कचरा और अपशिष्ट जल प्रबंधन दोनों ही नदियों की स्वच्छता और पुनर्जीवन के लिए जरूरी हैं। ऐसे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस व तरल कचरे के सुरक्षित निपटान पर केंद्रित स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं उसी भौगोलिक क्षेत्र में नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ काम कर सकती हैं। शहरी जल प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें जलापूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल निकासी की योजनाएं आपस में जुड़ी हों। इन क्षेत्रों में वर्तमान और भविष्य के शहरी विकास को ध्यान में रखकर पानी से जुड़े बुनियादी ढांचे को शहर के मास्टर प्लान के भूमि उपयोग योजना के अनुरूप बनाना चाहिए। कुछ राज्यों ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए भी हैं।

हमें यह समझना होगा कि सभ्यता के विकास में नदियां जीवन रेखा होने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ भी रही हैं। इन्हें बचाना और पुनर्जीवित करना न केवल नदियों, बल्कि मानव जाति को दूसरा जीवन देने जैसा है। उपचारित अपशिष्ट जल का दोबारा उपयोग करना एक ऐसा ही दृष्टिकोण है, जो नदियों की निर्मलता और अविरलता सुनिश्चित कर सकता है।